चिकित्सीय आपातकाल/एम्बुलेंस सेवा के लिए कृपया 112 पर डायल करें।

अण्डमान निकोबार द्वीप समाचार

रजि.न.34300/80 | संख्या 240 | श्री विजय पुरम, मंगलवार, 08 सितम्बर 2026 | web: dt.andamannicobar.gov.in | 2.00 रूपए

'सक्षम–सीपीएओ प्रशिक्षण शाखा' का शुभारंभ एवं आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च

श्री विजय पुरम, 7 सितंबर।

मुख्य वेतन एवं लेखा कार्यालय (सीपीएओ), अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन ने आज 'सक्षम–सीपीएओ की प्रशिक्षण शाखा' के उद्घाटन और आधिकारिक सीपीएओ वेबसाइट के शुभारंभ के साथ व्यावसायिक क्षमता को मजबूत करने तथा डिजिटल पहुंच को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव हासिल किया।

'सक्षम' का पूर्ण रूप 'लेखा एवं वित्तीय प्रबंधन से जुड़े मानव संसाधनों के लिए कौशल संवर्धन एवं ज्ञान सुदृढ़ीकरण' है। इसे सीपीएओ की एक समर्पित प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण पहल के रूप में परिकल्पित किया गया है। प्रशिक्षण शाखा का उद्देश्य लेखा, वित्त, वेतन एवं संबंधित प्रशासनिक कार्यों से जुड़े कर्मचारियों को संरचित अधिगम के अवसर प्रदान करना है, जिससे उनके पेशेवर ज्ञान, कौशल एवं कार्यकुशलता में वृद्धि हो सके।

कार्यक्रम में अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के वित्त सचिव श्री हेमंत कुमार, आईएएस, मुख्य अतिथि के रूप में और अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के लेखा एवं बजट निदेशक एवं मुख्य वेतन एवं लेखा अधिकारी श्री एस. दासगुप्ता सम्मानित अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

इस अवसर पर गणमान्य व्यक्तियों ने कुशल एवं पारदर्शी वित्तीय प्रशासन सुनिश्चित करने में निरंतर सीखने, कौशल विकास तथा प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग के महत्व पर प्रकाश डाला। इस पहल से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में एक सक्षम, ज्ञानवान एवं भविष्य के लिए तैयार कार्यबल तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान मिलने की उम्मीद है।

सोवटेक की सहायता से विकसित आधिकारिक सीपीएओ वेबसाइट **https://cpao.andamannicobar.gov.in** का भी इस अवसर पर शुभारंभ किया गया। यह वेबसाइट मुख्य वेतन एवं लेखा कार्यालय से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं, निर्देशों, अद्यतनों, प्रशिक्षण संबंधी संसाधनों एवं अन्य सेवाओं के प्रसार के लिए एक समर्पित डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगी।

'सक्षम' के माध्यम से सीपीएओ की ओर से सरकारी कर्मचारियों एवं लेखा तथा वित्तीय प्रबंधन से जुड़े हितधारकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं, व्यावहारिक प्रशिक्षण सत्र तथा अन्य ज्ञान–साझाकरण पहल आयोजित करने का प्रस्ताव है।

सीपीएओ ने 'सक्षम' को सीखने, ज्ञान के आदान–प्रदान एवं निरंतर व्यावसायिक विकास के लिए एक सतत मंच बनाने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की, जिससे अंततः पूरे द्वीपसमूह में सार्वजनिक वित्तीय प्रशासन में अधिक दक्षता एवं प्रभावशीलता लाने में योगदान मिल सके।

किसान आईडी और किसान रजिस्ट्री में नामांकन के लिए कृषि विभाग का व्यापक अभियान

श्री विजय पुरम, 7 सितंबर।

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के कृषि विभाग द्वारा पूरे अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में किसान आईडी बनाने तथा पात्र किसानों का किसान रजिस्ट्री में नामांकन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य किसानों की डिजिटल पहचान स्थापित करना तथा उन्हें पीएम–किसान और अन्य सरकारी योजनाओं, सब्सिडी, कृषि सेवाओं एवं लाभों तक सुगम पहुंच प्रदान करना है। विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारी पात्र किसानों की अधिकतम संख्या को कवर करने के लिए नामांकन शिविर आयोजित करने के साथ–साथ गांवों का दौरा भी कर रहे हैं। विभाग ने किसान रजिस्ट्री में 100 प्रतिशत संतृप्ति प्राप्त करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, ताकि प्रत्येक पात्र किसान का विधिवत पंजीकरण हो सके और वह विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के तहत उपलब्ध लाभों एवं सेवाओं का लाभ उठा सके।

क्षेत्रीय कर्मचारियों को नामांकन अभियान में तेजी लाने, पहुंच का विस्तार करने तथा व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, विशेष रूप से उन किसानों का, जिन्होंने अभी तक अपना पंजीकरण पूरा नहीं किया है। पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान किसानों को आने वाली कठिनाइयों को दूर करने तथा ऐसे मामलों का जल्द से जल्द समाधान करने के लिए समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि नामांकन प्रक्रिया सरल, सुलभ एवं परेशानी मुक्त हो सके। आरओआर और आधार में नाम में असंगति की समस्या के समाधान के लिए किसानों से अनुरोध किया गया है कि वे विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज़ एकत्र कर संबंधित सब–डिपो प्रभारियों के पास जमा करें, ताकि इस मामले को आगे राजस्व विभाग के समक्ष उठाया जा सके।

कृषि विभाग ने उन सभी पात्र किसानों से अपील की है, जिन्होंने अभी तक अपनी किसान आईडी नहीं बनाई है, कि वे अपने निकटतम कृषि सब–डिपो से संपर्क करें और जल्द से जल्द किसान रजिस्ट्री में अपना नामांकन पूरा करें।

किसानों को प्राथमिकता के आधार पर अपना पंजीकरण पूरा करने की सलाह दी गई है, क्योंकि किसान रजिस्ट्री में नामांकन पूरा नहीं करने पर आगामी रबी मौसम 2026 से रियायती उर्वरक, कृषि इनपुट तथा पीएम–किसान के लाभ बंद किए जा सकते हैं।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार विभाग ने सभी पात्र किसानों से क्षेत्रीय कर्मचारियों के साथ सहयोग करने तथा पूरे द्वीपसमूह में उपलब्ध कराई जा रही नामांकन सुविधाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया है, ताकि किसान रजिस्ट्री में 100 प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित किया जा सके।

गणेश पूजा समारोह–2026 की तैयारियों और कानून–व्यवस्था को लेकर दक्षिण अण्डमान ज़िला कार्यालय में बैठक हुई

श्री विजय पुरम, 7 सितंबर।

दक्षिण अण्डमान ज़िले में गणेश पूजा समारोह–2026 के आयोजन को लेकर तैयारियों एवं कानून–व्यवस्था संबंधी व्यवस्थाओं के संबंध में ज़िला कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। गणेश पूजा समारोह 14 सितंबर, 2026 से शुरू होकर मूर्तियों के विसर्जन के साथ संपन्न होगा। बैठक में विद्युत, अग्निशमन, एसवीपीएमसी, सूचना, प्रचार एवं पर्यटन तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ–साथ गणेश पूजा समितियों के अध्यक्ष एवं सचिव उपस्थित रहे। आयोजकों को अग्नि सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, कानून–व्यवस्था संबंधी अनुमति, बिजली एवं स्वच्छता के संबंध में प्रचलित नियमों एवं दिशा–निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए गए। समारोह के शांतिपूर्ण आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए विद्युत, अग्नि सुरक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस विभाग, पत्तन प्रबंध बोर्ड तथा एसवीपीएमसी सहित संबंधित विभागों को भी आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए।

उपायुक्त, दक्षिण अण्डमान से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार आयोजकों एवं प्रतिभागियों को सभी आवश्यक अनुमतियां एकल खिड़की के माध्यम से उपलब्ध कराने की सुविधा के लिए ज़िला नियंत्रण कक्ष में एक हेल्प–डेस्क/काउंटर स्थापित किया जा रहा है। पूजा समिति के सदस्यों के लिए निर्देश (कड़ाई से अनुपालन हेतु)

1. शराब अथवा किसी नशीले पदार्थ के प्रभाव में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को विसर्जन जुलूस में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पूजा समिति द्वारा पूरे जुलूस के दौरान निगरानी रखने एवं अनुशासन बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में स्वयंसेवकों की तैनाती की जाएगी।
2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप लाउडस्पीकर का उपयोग रात 10 बजे तक हर हाल में बंद कर दिया जाना चाहिए। किसी भी उल्लंघन की स्थिति में म्यूजिक सिस्टम तथा संबंधित वाहन को तत्काल ज़ब्त कर लिया जाएगा।
3. विसर्जन के लिए प्रत्येक मूर्ति के साथ केवल सीमित संख्या में व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। समिति यह सुनिश्चित करेगी कि इस निर्देश का कड़ाई से पालन किया जाए।

जीबी पंत अस्पताल में प्रयोगशाला जांचों के लिए 9 करोड़ रुपये मूल्य की उपभोग्य सामग्री की खरीद को स्वास्थ्य सेवा निदेशक की मंजूरी

श्री विजय पुरम, 7 सितंबर।

स्वास्थ्य सेवा निदेशक ने श्री विजय पुरम स्थित जीबी पंत अस्पताल में प्रयोगशाला जांचों के लिए रिएजेंट सहित 9 करोड़ रुपये मूल्य की उपभोग्य सामग्रियों की खरीद के लिए प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यय स्वीकृति (एए एंड ईएस) प्रदान की है। कुछ प्रयोगशाला रिएजेंट की अस्थायी कमी के कारण पिछले कुछ दिनों के दौरान श्री विजय पुरम स्थित जीबी पंत अस्पताल में कुछ प्रयोगशाला जांचें नहीं की जा सकीं।

विभाग द्वारा इस मामले का उचित रूप से समाधान कर लिया गया है और सभी आवश्यक निर्धारित औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आवश्यक रिएजेंट की आपूर्ति के लिए अब आपूर्ति आदेश जारी कर दिए गए हैं। आवश्यक रिएजेंट शीघ्र ही उपलब्ध होने की उम्मीद है, जिसके बाद प्रभावित प्रयोगशाला जांचों को पुनः शुरू कर सामान्य रूप से किया जाएगा।

यहां प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति में अतः आम जनता से नहीं घबराने की अपील की गई है। विभाग स्थिति पर करीबी नज़र रख रहा है और जीबी पंत अस्पताल में आवश्यक निदान सेवाओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय कर रहा है।

विशेष रूप से सक्षम शिक्षक ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त कर द्वीपसमूह का नाम रोशन किया

श्री विजय पुरम, 7 सितंबर।

कई सीमाओं और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, एक 'दिव्यांगजन' भी समाज में बदलाव ला सकता है और ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। यह सफलता की कहानी उत्तर व मध्य अण्डमान ज़िले के मायाबंदर स्थित राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के एक विशेष रूप से सक्षम शिक्षक की है, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति से सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उनका नाम श्री जे. प्रकाश राव है।

उनकी इस उपलब्धि पर सोमवार को अण्डमान लॉ कॉलेज के छात्रों ने यहां अपने सभागार में उनका अभिनंदन किया। अपने संबोधन में श्री प्रकाश राव ने दिव्यांगजन के रूप में अपने अनुभवों को साझा करते हुए उन्हें राष्ट्रीय महत्व से जोड़ा।

यहां प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि उन्होंने छात्रों से प्रत्येक चुनौती को जीवन स्तर को बेहतर बनाने के अवसर के रूप में लेने की अपील की। उन्होंने कहा, "मैंने प्रत्येक चुनौती को एक अवसर के रूप में लिया। सीमित गतिशीलता और सीमित संसाधनों के बावजूद, मैं शिक्षण के क्षेत्र में बदलाव लाने में सक्षम रहा।"

बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्राचार्य डॉ. पी.वी.एन. सरमा ने कहा कि श्री प्रकाश राव ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार–2026 जीतकर द्वीपसमूह और शिक्षण समुदाय का नाम रोशन किया है। पूजा पात्रो और सानिया ने कार्यक्रम का संचालन किया, जबकि तंजीला आरिफ ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

ज़िला स्तरीय "नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत" कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन

श्री विजय पुरम, 7 सितम्बर।

माई भारत, श्री विजय पुरम द्वारा 7 सितंबर, 2026 को श्री विजय पुरम स्थित टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय (टीजीसीई), के सभागार एवं सेमिनार हॉल में ज़िला स्तरीय "नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत" कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित विभिन्न ज़िला स्तरीय प्रतियोगिताओं एवं रचनात्मक गतिविधियों में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के लगभग 200 युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि, सम्मानित अतिथियों, विशिष्ट अतिथियों एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। यह विकसित भारत के निर्माण के लिए स्वस्थ, जागरूक एवं नशामुक्त युवा शक्ति के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रतीक था।

मुख्य अतिथि पद्मश्री पुरस्कार से विभूषित एवं स्वच्छ भारत के एम्बेस्डर श्री नरेश चन्द्र लाल ने अपने संबोधन में इस पहल की सराहना की तथा युवाओं को नशीले पदार्थों के दुरुपयोग से दूर रखने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि युवा राष्ट्र की शक्ति हैं और उनसे अपनी ऊर्जा, प्रतिभा एवं क्षमता को सकारात्मक गतिविधियों, सामाजिक ज़िम्मेदारी तथा राष्ट्र निर्माण की दिशा में लगाने का आह्वान किया। उन्होंने आगे कहा कि विकसित भारत के विजन को साकार करने के लिए स्वस्थ, अनुशासित एवं ज़िम्मेदार युवा आबादी आवश्यक है।

शेष पृष्ठ 3 पर

5वें स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए गए

नई दिल्ली, 7 सितम्बर (प.सू.का.)।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) ने आज स्वच्छ वायु दिवस 2026 का आयोजन किया। आज ही स्वच्छ आकाश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने मुख्य अतिथि के रूप में की। इस अवसर पर उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्तियों में सचिव (ईएफसीसी) श्री तन्मय कुमारय अध्यक्ष (सीएक्यूएम) श्री राजेश वर्माय महानिदेशक

शेष पृष्ठ 4 पर

अण्डमान तथा निकोबार पुलिस भर्तीः मायाबंदर में पीएम एंड ईटी 9 सितंबर से

मायाबंदर, 7 सितंबर। यह सूचित किया जाता है कि अण्डमान तथा निकोबार पुलिस भर्ती प्रक्रिया के तहत मायाबंदर पीएम एंड ईटी केंद्र पर शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक माप एवं सहनशक्ति परीक्षा (पीएम एंड ईटी) का आयोजन 9 सितम्बर, 2026 से 15 सितम्बर, 2026 तक नेताजी खेल परिसर, मायाबंदर में किया जाएगा।

अभ्यर्थियों के लिए सलाहः उत्तर व मध्य अण्डमान ज़िला पुलिस सभी अभ्यर्थियों को सलाह देती है कि वे अपने प्रवेश पत्र और अभ्यर्थी दिशानिर्देशों में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा निर्धारित रिपोर्टिंग तिथि एवं समय से काफी पहले परीक्षा स्थल पर उपस्थित हों।

अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने प्रवेश पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज़ों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां, अपने संबंधित पद या श्रेणी के अनुसार निर्धारित क्रम में व्यवस्थित/स्टेपल करके लाएं और मूल दस्तावेज़ साथ न लाएं:

1. आधार कार्ड
2. आवश्यक शैक्षणिक योग्यता/व्यवसाय प्रमाण–पत्र/आवश्यक अनुभव प्रमाण–पत्र
3. 10वीं/मैट्रिकुलेशन प्रमाण–पत्र–जन्म तिथि के प्रमाण के लिए
4. श्रेणी प्रमाण–पत्र
5. ड्राइविंग लाइसेंस

अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी पात्रता सिद्ध करने के लिए आवश्यक सभी दस्तावेज़ उपलब्ध हों और परीक्षा स्थल पर पहुंचने से पहले उन्हें उचित रूप से व्यवस्थित कर लिया गया हो।

किसी भी अभ्यर्थी को पीएम एंड ईटी में भाग लेने की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी, जब तक उसके पास निर्धारित वैध प्रमाण–पत्र/दस्तावेज़ 17 मई, 2026 को या उससे पहले के उपलब्ध न हों। निर्धारित कट–ऑफ तिथि के बाद प्राप्त या जारी किया गया कोई भी प्रमाण–पत्र/दस्तावेज़ भर्ती प्रक्रिया के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा, जहां भर्ती नियमों में अंतिम तिथि तक प्रमाण–पत्र/दस्तावेज़ का होना अनिवार्य निर्धारित किया गया है।

महत्वपूर्ण निर्देशः
अभ्यर्थियों को विशेष रूप से सलाह दी जाती है किः

- प्रवेश पत्र में उल्लिखित अपने निर्धारित दिनांक और रिपोर्टिंग समय पर ही उपस्थित हों।
- प्रवेश पत्र और आवश्यक स्वप्रमाणित दस्तावेज़ निर्धारित क्रम में साथ लाएं।
- पीएम एंड ईटी स्थल पर मोबाइल फोन या अन्य प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं साथ न लाएं।
- भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण के दौरान किसी भी अनुचित साधन का प्रयोग न करें और न ही उसका प्रयास करें।
- अनुशासन बनाए रखें और परीक्षा स्थल पर तैनात अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें।
- पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी साथ रखें और विशेष रूप से सहनशक्ति परीक्षा के दौरान शरीर में पानी की पर्याप्त मात्रा बनाए रखें।
- सत्यापन और अन्य औपचारिकताओं के लिए पर्याप्त समय मिल सके, इसके लिए काफी पहले रिपोर्ट करें।
- सिफारिशों, एजेंटों या बिचौलियों पर निर्भर रहने से बचें। चयन प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार और योग्यता के आधार पर सख्ती से संचालित की जाएगी।

उत्तर व मध्य अण्डमान पुलिस ने पीएम एंड ईटी के निष्पक्ष, पारदर्शी, सुव्यवस्थित और सुचारु संचालन के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की हैं, जिसका उद्देश्य प्रत्येक पात्र अभ्यर्थी को समान अवसर सुनिश्चित करना है।

अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे परीक्षा स्थल पर तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ सहयोग करें और भर्ती प्रक्रिया के सुचारु संचालन के लिए सभी निर्देशों का सख्ती से पालन करें।

सब्ज उत्पादन तकनीकों पर सात दिवसीय प्रशिक्षण के लिए 16 किसानों और 4 अधिकारियों की टीम पश्चिम बंगाल रवाना

श्री विजय पुरम, 7 सितंबर। अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के कृषि विभाग द्वारा उच्च मूल्य कृषि विकास एजेंसी (एचवीएडीए) के माध्यम से उत्तर व मध्य अण्डमान तथा दक्षिण अण्डमान के सब्ज उत्पादक क्षेत्रों से 16 किसानों और विभाग के 4 अधिकारियों की एक टीम को 8 से 14 सितंबर, 2026 तक पश्चिम बंगाल के नदिया ज़िले के कल्याणी स्थित आईसीएआर–केवीके में "सब्जियों की उत्पादन पद्धतियों एवं उत्पादन तकनीकों" पर आयोजित सात दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए भेजा गया है। यह प्रशिक्षण एमआईडीएच के तहत राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) के मानव संसाधन विकास (एचआरडी) घटक के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य प्रतिभागियों को आधुनिक एवं वैज्ञानिक सब्ज उत्पादन तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। प्रशिक्षण के प्रमुख क्षेत्रों में नर्सरी प्रबंधन, गुणवत्तापूर्ण बीज एवं रोपण सामग्री का चयन, फसल स्थापना, पोषक तत्व एवं जल प्रबंधन, एकीकृत कीट एवं रोग प्रबंधन, संरक्षित खेती, कटाई तथा कटाई उपरांत प्रबंधन शामिल हैं।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार इस कार्यक्रम से किसानों और क्षेत्रीय स्तर के अधिकारियों, दोनों की तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करने और अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में उन्नत एवं जलवायु अनुकूल सब्ज खेती की पद्धतियों को अपनाने को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस पहल के माध्यम से एचवीएडीए द्वीपसमूह में कृषि उत्पादकता बढ़ाने, कृषि उपज की गुणवत्ता में सुधार करने तथा टिकाऊ सब्ज उत्पादन को बढ़ावा देने के अपने प्रयास जारी रखे हुए है।

5वें स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान

पृष्ठ 1 का शेष

(वन) और विशेष सचिव (ईएफसीसी) श्री सुशील कुमार अवस्थीय अध्यक्ष (सीपीसीबी) श्री अमनदीप गर्गय और अवर सचिव (ईएफसीसी), श्री आशुतोष अग्निहोत्री शामिल थे। केंद्रीय मंत्रालयों और बहुपक्षीय संगठनों के अधिकारियों, पुरस्कार विजेता शहरों और वार्डों के महापौरों, ज़िला कलेक्टरों और नगर आयुक्तों के साथ–साथ एमओईएफसीसी, सीपीसीबी और सीएक्यूएम के अधिकारी भी उपस्थित थे।

इस अवसर पर अपने संबोधन में न्यायमूर्ति श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह देश भर के शहरों/वार्डों द्वारा वायु की गुणवत्ता को निर्धारित मानकों के भीतर बनाए रखने के लिए किए गए प्रयासों को मान्यता देने का अवसर है। उन्होंने कहा, "पुरस्कार विजेताओं ने यह सिद्ध किया है कि स्वच्छ वायु कोई आकांक्षा नहीं बल्कि एक व्यावहारिक लक्ष्य है जिसे उचित योजना और जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन से हासिल किया जा सकता है।" एनजीटी अध्यक्ष ने जोर देते हुए कहा कि स्वच्छ वायु एक मूलभूत आवश्यकता है, विलासिता नहीं। उन्होंने कहा, "विकास और पर्यावरण संरक्षण परस्पर विरोधी नहीं हैं, बल्कि नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए साथ–साथ चल सकते हैं। यह प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि आने वाली पीढ़ियों को रहने के लिए स्वच्छ वातावरण मिल सके।"

न्यायमूर्ति श्रीवास्तव ने वायु प्रदूषण को एक जटिल चुनौती बताया, क्योंकि प्रदूषण राजनीतिक सीमाओं को नहीं देखता और इसके कई स्रोत हैं। एनजीटी अध्यक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने वाली अग्रणी संस्थाएं शहरी/ग्रामीण स्थानीय निकाय हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों के माध्यम से सरकार वायु गुणवत्ता प्रबंधन के क्षेत्र में सभी हितधारकों के प्रयासों को मान्यता देती है, जो वायु गुणवत्ता को निर्धारित सीमा के भीतर बनाए रखने के लिए प्रयासरत हैं। उन्होंने यह भी कहा, "यह आवश्यक है कि स्थानीय निकाय नागरिकों को जागरूक करके प्रदूषण के स्रोत को ही रोकने का प्रयास करें, इस समस्या से निपटने के लिए नवीनतम तकनीकों को अपनाएं और इस मुद्दे के समाधान के लिए एक समावेशी और समग्र सामाजिक दृष्टिकोण अपनाएं।"

इस अवसर पर अपने संबोधन में, ईएफसीसी सचिव श्री तन्मय कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप, भारत सरकार वायु प्रदूषण से निपटने के लिए बहुआयामी, समन्वित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना रही है। वायु प्रदूषण से लड़ने में नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने और सभी हितधारकों के क्षमता विकास सुनिश्चित करने के लिए इस अभियान में जन प्रतिनिधियों को शामिल किया जा रहा है।

श्री कुमार ने एनसीएपी के बारे में बात की। एनसीएपी एक ऐसा ढांचा प्रदान करता है जिसके तहत शहरों को स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने के लिए अपनी रणनीतियां बनानी होती हैं, वहीं प्राण पोर्टल एनसीएपी के अंतर्गत आने वाले 130 शहरों के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन के विभिन्न मापदंडों पर नजर रखता है। उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण से निपटना एक सतत कार्यक्रम है, न कि एक बार का काम। आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ वातावरण हासिल करने के लिए नागरिकों के नेतृत्व में एक मिशन की आवश्यकता है। उन्होंने सभी पुरस्कार विजेताओं को उनके प्रयासों के लिए बधाई दी और उन्हें वायु गुणवत्ता प्रबंधन को जन–भागीदारी आंदोलन बनाने के लिए प्रोत्साहित किया।

स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार

इस अवसर पर, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहरों और वार्डों को पुरस्कृत किया, जिन्हें 5वें स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के तहत रैंकिंग दी गई थी। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण का ढांचा 2022–23 में जारी किया गया था, जिसमें शहरों द्वारा सड़क की धूल, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन, औद्योगिक प्रदूषण, निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन, अन्य उत्सर्जन (डीजी सेट और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान), और सूचना एवं संचार संचार (आईईसी) गतिविधियों पर उठाए गए उपायों का विवरण दिया गया था।

ये पुरस्कार 3 समूहों (3 लाख से कम जनसंख्याय 3–10 लाख जनसंख्या और 10 लाख से अधिक जनसंख्या) में सभी 130 शहरों की भागीदारी और रैंकिंग के आधार पर दिए गए थे। इस प्रक्रिया में शहरों द्वारा स्व–मूल्यांकन, राज्य स्तरीय निगरानी समिति द्वारा अनुमोदन, सीपीसीबी द्वारा मूल्यांकन, स्वतंत्र समितियों द्वारा क्षेत्रीय सत्यापन और 10 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहरों का चयन शामिल था।

पीएमएमएसवाई के सीआरसीएफवी के तहत 'समुद्री खाद्य पदार्थों से मूल्यवर्धित उत्पाद विकास' पर प्रशिक्षण शुरू

श्री विजय पुरम, 7 सितंबर। मत्स्य विभाग, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के जलवायु अनुकूल तटीय मछुआरा गांव (सीआरसीएफवी) कार्यक्रम के तहत 'समुद्री खाद्य पदार्थों से मूल्यवर्धित उत्पाद विकास' पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आज फिश लैंडिंग सेंटर (एफएलसी), पानीघाट में शुभारंभ किया गया। यह कार्यक्रम कोचीन स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग (एनआईएफपीएचएटीटी) के तकनीकी सहयोग से आयोजित किया जा रहा है।

सीआरसीएफवी कार्यक्रम, भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य कौशल विकास, विविधीकृत आजीविका गतिविधियों, टिकाऊ मत्स्य पालन प्रथाओं तथा मछली पकड़ने के बाद के प्रबंधन के माध्यम से तटीय मछुआरा समुदायों की आजीविका सुरक्षा एवं जलवायु अनुकूलन क्षमता को मजबूत करना है। इसमें मूल्यवर्धन के माध्यम से आजीविका के अवसर बढ़ाने पर विशेष ज़ोर दिया गया है।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में दक्षिण अण्डमान ज़िले के होप टाउन और जंगलीघाट तथा उत्तर व मध्य अण्डमान ज़िले के दुर्गापुर को सीआरसीएफवी गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए चिन्हित किया गया है। इन पहलों के तहत वर्तमान प्रशिक्षण कार्यक्रम 7 से 9 सितंबर, 2026 तक दक्षिण अण्डमान के होप टाउन गांव में तथा 11 से 13 सितंबर, 2026 तक डिगलीपुर के दुर्गापुर में आयोजित किया जा रहा है, ताकि प्रतिभागियों को समुद्री खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्धन में तकनीकी और व्यावहारिक कौशल प्रदान किया जा सके। इस प्रकार की पहल का उद्देश्य मत्स्य संसाधनों के बेहतर उपयोग को बढ़ावा देना, मछली पकड़ने के बाद होने वाले नुकसान को कम करना तथा मछुआरा समुदायों के लिए अतिरिक्त आय सृजन के अवसर पैदा करना है, विशेष रूप से छोटे स्तर पर मूल्यवर्धन एवं उद्यमिता के माध्यम से।

कार्यक्रम का उद्घाटन मत्स्य विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. के. गोपाल ने किया। इस अवसर पर होप टाउन की ज़िला परिषद सदस्य सुश्री वी. के. मरियम बीबी, ग्राम पंचायत होप टाउन की प्रधान श्रीमती रशीदा बीबी तथा होप टाउन के पंचायत समिति सदस्य श्री बी. लक्ष्मी नारायण अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समन्वय फिश लैंडिंग सेंटर, पानीघाट के प्रभारी श्री मोहम्मद फारूक ने सागर मित्रों के साथ किया। उद्घाटन सत्र के दौरान संयुक्त निदेशक (मत्स्य) ने मत्स्य पालन के बाद की तकनीक एवं मूल्यवर्धन के क्षेत्र में एक प्रमुख संस्थान एनआईएफपीएचएटीटी, कोचीन द्वारा दिए जा रहे विशेष प्रशिक्षण का प्रभावी उपयोग करने के महत्व पर ज़ोर दिया।

एनआईएफपीएचएटीटी, कोचीन के प्रोसेसिंग–कम–क्वालिटी एश्योरेंस सुपरवाइज़र डॉ. नितिन सी. टी. तथा प्रोसेसिंग–कम–क्वालिटी एश्योरेंस सुपरवाइज़र श्री बिनीश के. मुकुंदन तीन दिवसीय कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे मूल्यवर्धित समुद्री खाद्य उत्पादों के विकास के विभिन्न पहलुओं पर तकनीकी सत्र आयोजित कर विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं, जिसमें प्रसंस्करण तकनीक, उत्पाद तैयार करना, स्वच्छतापूर्ण रख–रखाव, गुणवत्ता आश्वासन तथा मछली पकड़ने के बाद की अन्य संबंधित प्रक्रियाएं शामिल हैं।

कार्यक्रम के दौरान एनआईएफपीएचएटीटी, कोचीन द्वारा ब्रांड किए गए विभिन्न मूल्यवर्धित समुद्री खाद्य उत्पादों, जिनमें फिश पिकल, फिश वेफर्स, स्मोक्ड फिश, डिब्बाबंद मछली तथा रेडी–टू–कुक तिलापिया करी आदि शामिल हैं, को भी प्रदर्शित एवं तैयार करने की प्रक्रिया का प्रदर्शन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभागियों को कम से कम 10 विभिन्न मूल्यवर्धित समुद्री खाद्य उत्पादों की तैयारी एवं विकास का व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिसमें ब्रेडेड एवं बैटर्ड उत्पाद, अचार, तले हुए उत्पाद तथा विभिन्न प्रकार की मछली आधारित करी शामिल हैं।

प्रशिक्षण के प्रथम दिन सभी 25 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण पुस्तिकाएं वितरित की गईं, ताकि उनके सीखने में सुविधा हो तथा प्रशिक्षण के दौरान प्रदान किए गए ज्ञान एवं तकनीकों के व्यावहारिक अनुप्रयोग में सहायता मिल सके।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार पीआरआई सदस्यों ने स्थानीय मछुआरा समुदाय को विशेष एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए मुख्यभूमि से तकनीकी विशेषज्ञों को लाने के लिए मत्स्य विभाग के प्रयासों की सराहना की।

रेड रन मैराथन के लिए संशोधित मार्ग की घोषणा

श्री विजय पुरम, 7 सितंबर। अण्डमान तथा निकोबार एड्स नियंत्रण सोसायटी (एएनएसीएस) ने 11 सितंबर, 2026 (शुक्रवार) को आयोजित होने वाली 5 किलोमीटर की रेड रन मैराथन के मार्ग और प्रारंभिक स्थल में बदलाव की घोषणा की है।

पुलिस भर्ती प्रक्रिया के कारण मैराथन के मार्ग में संशोधन किया गया है।

संशोधित मार्ग इस प्रकार होगाः
प्रारंभिक स्थल : जेएनआरएम–फ्लैग प्वाइंट–मज़ार–साइंस सेंटर–उसी मार्ग से वापस–जेएनआरएम में समापन।

यहां प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रतिभागी आरंभिक स्थल (जेएनआरएम के सामने) तक आरजीटी रोड, मच्छी लाइन रोड, साउथ प्वाइंट रोड अथवा कार्बाइंस कोव रोड के माध्यम से पहुंच सकते हैं, क्योंकि उपर्युक्त भर्ती प्रक्रिया के कारण आयोजन स्थल तक पहुंचने वाले अन्य सभी मार्ग अवरुद्ध हो सकते हैं। रेड रन मैराथन से संबंधित अन्य सभी विवरण यथावत रहेंगे।

मादक पदार्थ रोधी अभियान में डिगलीपुर से दो आरोपी गिरफ्तार

मायाबंदर, 7 सितंबर। उत्तर व मध्य अण्डमान ज़िला पुलिस ने मादक पदार्थों के विरुद्ध अपने निरंतर प्रवर्तन अभियान को जारी रखते हुए 5 सितंबर, 2026 को दो महत्वपूर्ण कार्रवाई की।

विश्वसनीय सूचना के आधार पर, पुलिस की एक टीम ने डिगलीपुर थाने के प्रभारी उपनिरीक्षक मोहम्मद रफीक के नेतृत्व में सुभाषग्राम के निकट एक व्यक्ति को रोका और उसके कब्ज़े से लगभग 104 ग्राम संदिग्ध गांजा बरामद किया। एक अन्य कार्रवाई में सागर द्वीप में पुलिस ने एक निवासी के मकान के पीछे उगाए गए चार संदिग्ध गांजे के पौधे बरामद किए। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया तथा डिगलीपुर थाने में स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (एनडीपीएस अधिनियम) की संबंधित धाराओं के तहत मामले दर्ज़ किए गए हैं। प्रतिबंधित मादक पदार्थों के स्रोत का पता लगाने और इसमें शामिल अन्य व्यक्तियों की पहचान करने के लिए आगे की जांच जारी है।

उत्तर व मध्य अण्डमान ज़िला पुलिस मादक पदार्थों की तस्करी के प्रति शून्य–सहिष्णुता की नीति अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है। खुफिया सूचना के आधार पर कार्रवाई और कड़ी कानूनी कार्रवाई पूरे ज़िले में जारी रहेगी।

उत्तर व मध्य अण्डमान के पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति में आम जनता से 100 या 112 पर अथवा निकटतम पुलिस थाने में मादक पदार्थों से संबंधित गतिविधियों की सूचना देने का आग्रह किया गया है। सूचनादाताओं की पहचान गोपनीय रखी जाएगी तथा कार्रवाई योग्य सूचना देने वाले व्यक्तियों को उपयुक्त पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।

मौसम संबंधी पूर्वानुमान

श्री विजय पुरम, 7 सितंबर। 8 सितंबर से 13 सितंबर, 2026 तक अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में एक या दो स्थानों पर गरज के साथ बिजली चमकने और तेज हवाएं (गति 30–40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने) की बहुत अधिक संभावना है। आपदा प्रबंधन निदेशालय से प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि 8 सितम्बर, 2026 को 11.30 बजे तक 17.0–19.0 सेकंड की अवधि और 1.2–1.3 मीटर ऊंचाई वाली स्वेल तरंगों का पूर्वानुमान है। इसमें सलाह दी गई है कि लहरों के उफान मारने की संभावना है। नौकाओं का संचालन अत्यधिक सतर्कता के साथ किया जाए और मनोरंजन संबंधी गतिविधियां उचित सावधानी के साथ की जाएं।

सूचना, प्रचार और पर्यटन निदेशालय द्वारा प्रकाशित तथा प्रबन्धक, राजकीय मुद्रणालय द्वारा मुद्रित, वितरण तथा विज्ञापन के लिए फोन–229465, प्रधान सम्पादक (प्रभारी) पी. कैरल डी. सोणी
e-mail:dweepsamachar@gmail.com

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
सचिवालय

अधिसूचना

श्री विजय पुरम, दिनांक 04 सितम्बर, 2026

सं. 255/2026 फा. सं. 2–116/2026–राजस्व, जनगणना नियमावली, 1990 के नियम–8 (iaa) के साथ पठित भारत सरकार, गृह मंत्रालय के दिनांक 14.08.2026 के पत्र सं. 9/10/2025-CD (Cen.) के अनुसरण में, भारत के राजपत्र में प्रकाशित, दिनांक 14 अगस्त, 2026 की अधिसूचना संख्या का.आ. 4505 (अ). को एतद्वारा आम जनता की सूचना हेतु पुनः प्रकाशित किया जाता है।

ह./–
सहायक सचिव (राजस्व)
अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन

गृह मंत्रालय
(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 14 अगस्त, 2026

का.आ. 4505 (अ).– केन्द्रीय सरकार, जनगणना अधिनियम, 1948 (37 का 1948) की धारा 8 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुदेश और निर्देश देती है कि भारत की जनगणना 2027 के संबंध में परिवार अनुसूची के माध्यम से जानकारी एकत्रित करने के लिए, जनगणना अधिकारी उन स्थानीय क्षेत्र की सीमाओं के भीतर जिनके लिए उन्हें क्रमशः नियुक्त किया गया है, उन सभी सीमाओं के भीतर रहने वाले सभी व्यक्तियों से नीचे सूचीबद्ध मदों के संबंध में सभी ऐसे प्रश्न पूछ सकता है, अर्थात :

1. व्यक्ति का नाम
2. मुखिया से संबंध
3. लिंग
4. जन्म तिथि और आयु (पूर्ण वर्षों में)
5. वर्तमान वैवाहिक स्थिति
6. विवाह के समय आयु (पूर्ण वर्षों में)
7. पति/पत्नी का नाम
8. घोषित राष्ट्रीयता
9. धर्म
10. अनुसूचित जाति (अ.जा.)/अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.)/जाति
11. पिता का विवरण
12. माता का विवरण
13. निःशक्तता
14. मातृभाषा एवं अन्य भाषाओं का ज्ञान
15. साक्षरता एवं डिजिटल साक्षरता की स्थिति
16. शैक्षणिक संस्थान में शिक्षा ग्रहण की स्थिति
17. प्राप्त शिक्षा का उच्चतम स्तर तथा संकाय/विषय
18. पिछले वर्ष किसी भी समय कोई कामकाज किया
19. आर्थिक कार्यकलाप की श्रेणी
20. व्यवसाय
21. उद्योग, व्यापार अथवा सेवा का स्वरूप
22. कर्मी का वर्ग
23. गैर–आर्थिक कार्यकलाप (अल्पकालिक, अर्द्ध–अल्पकालिक और गैर कर्मी के लिए)
24. काम की खोज में अथवा काम के लिए उपलब्ध (अल्पकालिक, अर्द्ध–अल्पकालिक और गैर कर्मी के लिए)
25. कार्यस्थल तक की यात्रा
26. जन्म स्थान
27. पूर्व निवास स्थान
28. स्थान परिवर्तन का कारण
29. स्थान परिवर्तन के पश्चात इस गाँव/नगर में निवास की अवधि
30. स्थायी निवास स्थान का पता
31. वर्तमान में जीवित बच्चों की संख्या (केवल वर्तमान में विवाहित, विधवा, तलाकशुदा और संबंध विच्छेदित महिला के लिए)
32. कभी भी जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या (केवल वर्तमान में विवाहित, विधवा, तलाकशुदा और संबंध विच्छेदित महिला के लिए)
33. पिछले एक वर्ष के दौरान जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या (केवल वर्तमान में विवाहित महिला के लिए)
34. कोविड़–19 टीकाकरण का स्थान
35. बैंक खातों की कुल संख्या
36. मोबाइल नंबर (यदि उपलब्ध हो)
37. आधार नंबर (यदि उपलब्ध हो)
38. वोटर आईडी नंबर (यदि उपलब्ध हो)
39. पासपोर्ट नंबर (यदि भारतीय पासपोर्ट धारक हैं)
40. ड्राइविंग लाइसेंस की उपलब्धता

{फा. सं. 9/8/2025–सीडी (सीइएन)}

मृत्युंजय कुमार नारायण, भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त

ई–निविदा सूचना

F.No. Proc-214/4/2023-JR ASST (TSM)-ANIIDCO_AN/2354 दिनांक 02.09.2026

डॉलफिन बीच रिसॉर्ट के लिए खाद्य सामग्रियों (गैर–एमआरपी) की आपूर्ति हेतु ऑनलाइन ई–निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

निविदा के नियम और शर्तों युक्त दस्तावेज वेबसाइट https://eprocure.andamannicobar.gov.in से डाऊनलोड कर सकते हैं अथवा वरिष्ठ प्रबंधक (पर्यटन), अनिडको, विकास भवन, श्री विजय पुरम से भी सभी कार्य दिवसों के दौरान दिनांक 21.09.2026 के सायं 5.00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।

निविदा दिनांक 22.09.2026 को पूर्वाहन 11.00 बजे तक ऑनलाइन https://eprocure.andamannicobar.gov.in पर भरी जानी चाहिए और दस्तावेज मुहरबंद लिफाफे में रखकर निगमित कार्यालय स्थित टेंडर बॉक्स में दिनांक 22.09.2026 को दोपहर 12.00 बजे तक डाल दें, और तकनीकी बोली उसी दिन सायं 4.00 बजे निविदादाताओं या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधिगणों के समक्ष खोला जाएगा।

निगम के महाप्रबंधक (पर्यटन) के पास किसी भी निविदा को स्वीकार करने अथवा सभी को बिना कोई कारण बताए रदद् करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

महाप्रबंधक (पर्यटन), अनिडको

खाड़ी की अस्थिरता के बीच विदेशी चावल खरीदार अब सीधे भारत का कर रहे रुख

नई दिल्ली, 07 सितम्बर।

वैश्विक चावल व्यापार में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस के एक सर्वे में सामने आया है कि विदेशी चावल खरीदार अब सीधे भारत आकर देश के प्रोडक्शन, मिलिंग, प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट इकोसिस्टम तक पहुंच बनाना पसंद कर रहे हैं।

सर्वे के अनुसार, खाड़ी क्षेत्र में बढ़ती जियोपॉलिटिकल अस्थिरता कॉर्पोरेट यात्रा और सोर्सिंग के तरीकों पर सीधा असर डाल रही है। BIRC 2026 के लिए रजिस्टर्ड विदेशी खरीदारों में से करीब 37 प्रतिशत ने माना कि खाड़ी की अस्थिरता ने अंतरराष्ट्रीय ट्रेड इवेंट्स में भाग लेने के उनके फैसलों को प्रभावित किया है। यह कॉन्फ्रेंस 23 अक्टूबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होने वाली है।

30 अगस्त तक BIRC ने 138 देशों के 3,317 इंटरनेशनल खरीदारों का रजिस्ट्रेशन दर्ज किया है। बांग्लादेश 336 खरीदारों के साथ सबसे आगे है, उसके बाद बेनिन (179) और नाइजीरिया (177) का स्थान है। UAE से 145, नेपाल और फिलीपींस से 137–137, इथियोपिया से 127, सऊदी अरब से 125 तथा इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका से 109–109 खरीदारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है।

व्यापार की मौजूदा तस्वीर बताती है कि कंपनियां बाजार में आने वाली रुकावटों से निपटने के लिए प्रोडक्शन हब के करीब कई खास सोर्सिंग पॉइंट बना रही हैं। जहां दुबई में 'गल्फूड' जैसे प्लेटफॉर्म बड़े अंतरराष्ट्रीय एग्जीबिशन आयोजित करते रहते हैं, वहीं खास कमोडिटी मीटिंग्स व्यापार में सीधा संपर्क बनाने का बेहतर मौका देती हैं। भारतीय चावल व्यापार के लिए खरीदार और विक्रेता के बीच व्यवस्थित संबंध बनाने की क्षमता ग्लोबल मार्केट में बार–बार व्यापार के रिश्ते मजबूत करने का रास्ता खोलती है।

अंतरराष्ट्रीय ट्रेड नेटवर्क की कड़ी जांच–पड़ताल हो रही है क्योंकि लंबे समय से चले आ रहे जियोपॉलिटिकल जोखिम पारंपरिक क्षेत्रीय मीटिंग पॉइंट की परीक्षा ले रहे हैं। ईरान संघर्ष का असर फूड सेक्टर से आगे बढ़कर कमर्शियल यात्रा पर भी पड़ा है। जेपी मॉर्गन और पार्टनर्स ग्रुप जैसी कंपनियों ने इस साल की शुरुआत में UAE में होने वाली मीटिंग्स को दूसरी जगह शिफ्ट किया या रद्द कर दिया। एविएशन में रुकावटों के कारण मार्च में दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई। अमेरिका ने UAE के लिए लेवल 3 की "यात्रा पर पुनर्विचार करें" एडवाइजरी जारी रखी है, जिसका कारण सशस्त्र संघर्ष, ड्रोन और मिसाइल का खतरा तथा उड़ान संबंधी दिक्कतें हैं। रिपोर्टों के मुताबिक, तनाव बढ़ने के कारण UAE ने पिछले महीने के आखिर में ईरान के साथ व्यापार, कमर्शियल लेन–देन और वित्तीय लेनदेन रोक दिए थे।

8 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस?

नई दिल्ली, 07 सितम्बर।

हर साल 8 सितंबर को दुनियाभर में अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य केवल लोगों को पढ़ना–लिखना सिखाने की जरूरत बताना नहीं है, बल्कि यह याद दिलाना भी है कि साक्षरता शिक्षा, अवसर, आत्मनिर्भरता और सामाजिक भागीदारी की बुनियाद है। साल 2026 इस दिवस के लिए खास है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस की शुरुआत के 60 वर्ष पूरे हो रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस की तारीख के पीछे एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाक्रम है। 1965 में ईरान के तेहरान में शिक्षा मंत्रियों का विश्व सम्मेलन आयोजित हुआ था, जिसमें निरक्षरता खत्म करने और दुनिया भर में साक्षरता बढ़ाने पर जोर दिया गया। इसके बाद यूनेस्को ने 1966 में अपने 14वें जनरल कॉन्फ्रेंस में 8 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया, जिसे पहली बार यह दिवस 8 सितंबर 1967 को मनाया गया। तब से हर साल 8 सितंबर को दुनियाभर में साक्षरता के महत्व को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

इस साल अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम, "Literacy for people, the planet and prosperity" है हिंदी में इसका अर्थ है, "लोगों, पृथ्वी और समृद्धि के लिए साक्षरता। यह थीम साक्षरता को केवल पढ़ने और लिखने की क्षमता तक सीमित नहीं रखती। इसका संबंध बेहतर जीवन, सामाजिक समावेशन, टिकाऊ विकास और आर्थिक अवसरों से भी है। यूनेस्को के अनुसार 2026 का आयोजन इस बात पर विचार करने का अवसर है कि पिछले छह दशकों में साक्षरता के क्षेत्र में कितनी प्रगति हुई और अब भी कौन–सी पुरानी तथा नई चुनौतियां मौजूद हैं।

2026 में अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस की 60वीं वर्षगांठ है। इस मौके पर न्छम्ैब्द और मेक्सिको सरकार की ओर से 8 और 9 सितंबर को मेक्सिको के चियापास में वैश्विक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री, विशेषज्ञ, शिक्षक, विद्यार्थी और साक्षरता के क्षेत्र में काम करने वाले विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। कार्यक्रम में वैश्विक साक्षरता की प्रगति, मौजूदा चुनौतियों और भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा होगी।

किसी व्यक्ति का नाम पढ़ लेना या किसी वाक्य को लिख लेना साक्षरता का पहला चरण हो सकता है, लेकिन आधुनिक दुनिया में इसकी भूमिका इससे कहीं बड़ी हो चुकी है। आज साक्षर व्यक्ति को जानकारी समझने, सही निर्णय लेने, रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने और समाज में अपनी बात रखने के लिए भी पढ़ने–लिखने की क्षमता की जरूरत होती है। डिजिटल युग में साक्षरता का संबंध डिजिटल जानकारी को समझने, ऑनलाइन उपलब्ध सूचनाओं का सही इस्तेमाल करने और गलत जानकारी से बचने से भी जुड़ गया है। यही कारण है कि साक्षरता को व्यक्ति के सशक्तीकरण और सामाजिक भागीदारी से जोड़कर देखा जाता है।

भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में साक्षरता का महत्व और भी बढ़ जाता है। शिक्षा केवल रोजगार का रास्ता नहीं खोलती, बल्कि व्यक्ति को अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझने में सक्षम बनाती है। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस के मौके पर यूनेस्को की ओर से अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार भी दिए जाते हैं। इन पुरस्कारों का उद्देश्य ऐसे कार्यक्रमों और पहलों को पहचान देना है, जिन्होंने साक्षरता को बढ़ाने और लोगों को सशक्त बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप्स के लिए खुला है अमेरिकी बाजार, चंद्रमा मिशन में भारत के साथ साझेदारी चाहता है अमेरिका–सर्जियो गोर

नई दिल्ली, 7 सितंबर (आईएएनएस)।

भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने सोमवार को कहा कि अमेरिकी बाजार भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप्स के लिए पूरी तरह खुला है और अमेरिकी निवेशक भारत के तेजी से बढ़ते स्पेस सेक्टर पर करीबी नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने संकेत दिया कि चंद्रमा पर स्थायी मानव उपस्थिति की दिशा में अमेरिका की महत्वाकांक्षी योजनाओं में भारत एक महत्वपूर्ण साझेदार बन सकता है।

बेंगलुरु स्पेस एक्सपो 2026 को संबोधित करते हुए गोर ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ अंतरिक्ष सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता है। उन्होंने बताया कि नासा ने आधिकारिक रूप से इसरो को अपने मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया है।

उन्होंने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम चंद्रमा पर वापस जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि भारत चंद्रमा की सतह पर हमारे साथ खड़ा हो। भारतीय स्पेस स्टार्टअप्स को संबोधित करते हुए गोर ने कहा कि अब उनके लिए वैश्विक अवसरों के द्वार तेजी से खुल रहे हैं। उन्होंने कहा, इस कक्ष में मौजूद प्रत्येक भारतीय अंतरिक्ष उद्यमी से मैं कहना चाहता हूं कि अमेरिकी बाजार आपके लिए खुला है। हमारे निवेशक आपको देख रहे हैं और हमारा नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र आपका स्वागत करता है।

उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच अंतरिक्ष साझेदारी एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। हाल ही में आयोजित नौवें भारत–अमेरिका असैनिक अंतरिक्ष संयुक्त

कार्य समूह की बैठकों का उल्लेख करते हुए गोर ने कहा कि दोनों देशों का सहयोग अब केवल डेटा साझा करने तक सीमित नहीं है।

उन्होंने कहा, हमारा संबंध अब महज सहयोग का नहीं बल्कि सह–निर्माण का है। हम केवल जानकारी साझा नहीं कर रहे, बल्कि उपकरणों का संयुक्त विकास कर रहे हैं, स्टार्टअप्स को संयुक्त रूप से वित्तीय सहायता दे रहे हैं और मानवता की अगली वैज्ञानिक उपलब्धियों का भविष्य साथ मिलकर लिख रहे हैं।

गोर ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र अब केवल राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का प्रतीक नहीं रह गया है, बल्कि यह वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख इंजन बन चुका है। नेविगेशन, संचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उन्नत विनिर्माण और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों की प्रगति अब अंतरिक्ष तकनीकों पर निर्भर होती जा रही है।–आईएएनएस

नीति आयोग ने प्लेटफ़ॉर्म फॉर एग्रीगेटिंग क्लीन ट्रांसपोर्ट किया लॉन्च

नई दिल्ली, 07 सितम्बर।

नीति आयोग की पहल 'ई–फास्ट इंडिया' ने देश में शून्य–उत्सर्जन माल ढुलाई को गति देने के लिए आज 'प्लेटफ़ॉर्म फॉर एग्रीगेटिंग क्लीन ट्रांसपोर्ट' यानी 'पैक्ट' लॉन्च किया। नई दिल्ली में आयोजित 5वें ई–फास्ट इंडिया शिखर सम्मेलन के दौरान नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने इस मंच की शुरुआत की। यह प्लेटफ़ॉर्म माल भेजने वालों, लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाताओं और वाहन निर्माताओं को एक साथ लाएगा, जिससे भारी इलेक्ट्रिक वाहनों और ई–ट्रकों के व्यावसायिक उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। सम्मेलन में 'जेट मार्केटप्लेस' की भी शुरुआत की गई, जो ई–ट्रक निर्माताओं और फाइनेंसरों को व्यापारिक साझेदारियों के लिए एक साझा मंच देगा। शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा कि भारत ने घरेलू स्तर पर ईवी निर्माण में बड़ी प्रगति की है। उन्होंने जोर दिया कि ई–ट्रकों को तेजी से अपनाने के लिए वित्तीय मॉडल और चार्जिंग के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना होगा। इस अवसर पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव वी. उमाशंकर ने कहा कि बढ़ती मांग को देखते हुए भारत एक मजबूत इलेक्ट्रिक ट्रकिंग इकोसिस्टम बनाने के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि बैटरी हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे नए उपाय इस क्षेत्र में पारदर्शिता लाएंगे और निवेश जोखिम को कम करेंगे।

भारत को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा के माध्यम से सालाना एक करोड़ पर्यटकों को लक्षित करना चाहिए–केन्द्रीय मंत्री

नई दिल्ली, 7 सितंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने सोमवार को भारत के चिकित्सा मूल्य पर्यटन इकोसिस्टम को मजबूत करने और उच्चतम गुणवत्ता मानकों के साथ अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य और कल्याण सेवाओं के प्रवेश द्वार के रूप में देश को स्थापित करने के लिए पांच सूत्रीय कार्य योजना पेश की। राष्ट्रीय राजधानी में भारत हेल्थ ग्लोबल एक्सपो 2026 में संजीवनी 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए गोयल ने कहा कि देश को सालाना गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा के इच्छुक 1 करोड़ पर्यटकों को लक्षित करना चाहिए।

पांच सूत्रीय कार्य योजना के बारे में बताते हुए गोयल ने कहा कि पहली प्राथमिकता देखभाल करने वालों को प्रशिक्षित और प्रमाणित करना एवं अंतरराष्ट्रीय मानकों की स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में सक्षम कुशल कार्यबल विकसित करना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि दूसरा बिंदु यह होना चाहिए कि अधिक से अधिक अस्पतालों को हील इन इंडिया गेटवे में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और ईमानदार एवं पारदर्शी उपचार पैकेज सामने लाए जाएं।

उन्होंने जोर देकर कहा कि अस्पतालों को नैतिक तौर–तरीकों का पालन करना चाहिए और कभी भी रोगियों को धोखा देने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक गलत कार्रवाई से भारत के लिए सद्भावना, व्यवसाय और विश्वसनीयता का नुकसान हो सकता है।

तीसरे बिंदु के रूप में, गोयल ने बीमाकर्ताओं और स्वास्थ्य–तकनीक कंपनियों से ऐसे उत्पाद और प्लेटफॉर्म बनाने का आह्वान किया जो रोगी की यात्रा को अधिक सहज बनाते हैं, समय पर प्रतिपूर्ति और कैशलेस भुगतान की अधिक उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि टेलीकंसल्टेशन और टेलीमेडिसिन को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा पर्यटन संबंधी आवागमन के प्रारंभिक हिस्से के रूप में बड़े पैमाने पर शामिल किया जा सकता है।

चौथा बिंदु दुनिया भर में प्रदर्शनियों और प्रस्तुतियों को आयोजित करने, विश्व स्तर पर अस्पतालों के साथ सुविधाप्रदाताओं को जोड़ने के साथ–साथ यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि केवल अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएच) द्वारा सक्षम, सत्यापित और पैनल वाले अस्पतालों को विदेश से आने वाले रोगियों के इलाज की अनुमति दी जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि एनएबीएच को बिना किसी कमी के साथ उच्चतम मानकों को बनाए रखना चाहिए। पांचवें बिंदु के रूप में, पीयूष गोयल ने राज्यों से अस्पतालों और कल्याण केंद्रों में गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने, अपने नेटवर्क का विस्तार करने, विश्व स्तर पर अच्छी गुणवत्ता वाली सुविधाएं तैयार करने और रोगियों के कल्याण के लिए इन सुविधाओं का विपणन करने का आग्रह किया। –आईएएनएस

इतिहास के पन्नों में 08 सितंबरः साइंस–फिक्शन के दीवानों के लिए खास तारीख

नई दिल्ली, 07 सितम्बर (हि.स.)।

देश–दुनिया के साइंस–फिक्शन यानी साई–फाई शोज के दीवानों के लिए 08 सितंबर की तारीख खास है। 1966 में इसी तारीख को अमेरिकी चैनल एनबीसी पर स्टार ट्रैक सीरीज का पहला एपिसोड टेलीकास्ट किया गया था। शुरुआत में इस सीरीज के केवल तीन सीजन ही बनाए गए। यह इतने पॉपुलर हुए कि स्टार ट्रैक अमेरिकी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का सबसे फेमस ब्रांड बन गया।

स्टार ट्रैक राइटर और प्रोड्यूसर जीन रॉडनबरी के दिमाग की उपज है। जीन राइटर से पहले एयरफोर्स पायलट थे। उन्होंने 23वीं सदी के आविष्कारों को ध्यान में रखकर स्टार ट्रैक को तैयार किया था। यूनाइटेड फेडरेशन ऑफ प्लेनेट्स ने स्टारशिप यूएसएस एंटरप्राइज बनाया था, जिसके क्रू मेंबर्स के स्पेस एक्सप्लोरेशन के एडवेंचर्स पर इस शो की कहानी आगे बढ़ती है। शुरुआत में बने तीन सीजन को फिलहाल ओरिजिनल सीरीज नाम से जाना जाता है। स्टार ट्रैक की ओरिजिनल सीरीज के अलावा नौ स्पिन–ऑफ टीवी सीरीज और 6 फिल्मों की एक फिल्म फ्रेंचाइजी भी शामिल है। कई मीडिया में इसके अलग–अलग एडॉप्टेशन भी हुए हैं।

महत्वपूर्ण घटनाचक्र–1271– जॉन XXI का पोप के रूप में चयन।

1320– गाजी मलिक दिल्ली का सुल्तान बना।

1331– स्टीफन उरोस चतुर्थ ने खुद को सर्बिया का राजा घोषित किया।

1449– टुमू किले के युद्ध में मंगोलिया ने चीन के सम्राट को बंधक बनाया।

1563– मैक्सीमिलियन को हंगरी का राजा चुना गया।

1900– टेक्सास के गैलवेस्टोन में चक्रवाती और ज्वारीय तूफान से 6000 लोगों की मौत

1952– जेनेवा में कॉपीराइट के लिये पहले विश्व सम्मेलन में भारत समेत 35 देशों ने किए हस्ताक्षर।

1962– चीन ने भारत की पूर्वी सीमा में घुसपैठ की।

1988– जाने–माने व्यवसायी विजयपत सिंघानिया अपने माइक्रो लाइट सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट से लंदन से अहमदाबाद पहुंचे।

1998– साल 2001 में निर्धारित 13वें गुट निरपेक्ष आंदोलन की मेजबानी बांग्लादेश को सौंपी गई।

2000– तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र शांति शिखर सम्मेलन के दौरान हिन्दी में भाषण देते हुए पाकिस्तान को फटकार लगाई।

2006– महाराष्ट्र के नासिक जिले में मालेगांव बम धमाके।

2008– प्रसिद्ध अमेरिका पत्रिका फोर्ब्स ने भारतीय अरबपति लक्ष्मी मित्तल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने की घोषणा की।

2009– भारत ने विमानवाहक पोत एडमिरल गोर्शकोव को नए कलपुर्जे लगाकर तैयार करने के लिए रूस को 10 करोड़ 20 लाख डालर दिए।

ज़िला स्तरीय "नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत" कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन ———— पृष्ठ 1 का शेष

टीजीसीई की प्राचार्या श्रीमती मंजुलता राव ने सम्मानित अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई तथा युवाओं को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के विरुद्ध जागरूकता फैलाने के साथ–साथ अपनी रचनात्मकता एवं प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए सार्थक मंच उपलब्ध कराने हेतु माई भारत की सराहना की।

पशुपालन विभाग के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुभाष पालवे विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने प्रतिभागी युवाओं को सकारात्मक बदलाव के दूत बनने तथा स्वस्थ एवं नशामुक्त समाज के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया।

इसरो के प्रबंधक श्री देवदास पाइक ने भी सभा को संबोधित किया और नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के हानिकारक शारीरिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक परिणामों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने युवाओं को अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखने, स्वस्थ आदतें अपनाने तथा अपने ज्ञान एवं क्षमता का रचनात्मक उद्देश्यों के लिए उपयोग करने के लिए प्रेरित किया।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के इतिहासकार श्री मुकेश्वर लाल ने भी इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए तथा युवाओं के बीच सकारात्मक सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने युवाओं को अपनी जड़ों से जुड़े रहने, रचनात्मक आदतें अपनाने तथा एक ज़िम्मेदार एवं प्रगतिशील समाज के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया।

कार्यक्रम में आठ ज़िला स्तरीय प्रतियोगिताओं–लोक संगीत, नृत्य, नुक्कड़ नाटक/मूक अभिनय, चित्रकला, भाषण, लघु फिल्म/रील, नारा लेखन एवं स्लैम कविता–में उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई। इन रचनात्मक माध्यमों के जरिए युवा प्रतिभागियों ने विकसित भारत के लिए नशामुक्त युवा का संदेश प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया।

लोक संगीत प्रतियोगिता में एनकॉल की एप्रियन एवं टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि जेसिका एवं टीम ने द्वितीय स्थान और टीजीसीई की धरजानी एवं टीम ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।

नृत्य प्रतियोगिता में वीकेवी की जान्हवी त्रिवेदी एवं टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि टीजीसीई के अनिश एवं टीम ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया।

नुक्कड़ नाटक/मूक अभिनय प्रतियोगिता में टीजीसीई की सुषमा एवं टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। डी. लेखा एवं टीम ने द्वितीय स्थान तथा पूजा एवं टीम ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।

चित्रकला प्रतियोगिता में एनकॉल की जीविता एस. ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि काव्या राज ने द्वितीय स्थान और टीजीसीई की रिक्ता बिस्वास ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।

भाषण प्रतियोगिता में टीजीसीई की संतोषी कुमारी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि उदय ने द्वितीय स्थान और पी. एलकीया ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।

लघु फिल्म/रील प्रतियोगिता में टीजीसीई के एमडी. तंजीम एवं टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि सुद्वीप बिस्वास एवं टीम ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया।

नारा लेखन प्रतियोगिता में टीजीसीई की प्रीति साहा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि डी. लेखा ने द्वितीय स्थान और श्रिते मंडल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।

स्लैम कविता प्रतियोगिता में टीजीसीई की नूपुर नवलाडेर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि जेएनआरएम की अभिनया ने द्वितीय स्थान और वी. मोहिता ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।

प्रतियोगिताओं का मूल्यांकन कला, संस्कृति, साहित्य, रंगमंच, संगीत, मीडिया एवं सामाजिक सेवा के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रतिष्ठित निर्णायक मंडल के सदस्यों द्वारा किया गया।

चित्रकला प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में वाणिज्यिक कलाकार श्री अशोक कुमार मिस्त्री, कलाकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती संपदा बनर्जी तथा पेशेवर कलाकार श्रीमती नागर लक्ष्मी शामिल थीं।

नृत्य प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में नृत्य शिक्षिका श्रीमती सुजाता, नृत्य शिक्षक श्री बालाकृष्ण तथा नृत्य शिक्षिका श्रीमती वी. पी. भवनेस शामिल थीं।

नुक्कड़ नाटक/मूक अभिनय प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में आर्ट ऑफ लिविंग के गुरुजी श्री रविंदर राव, रंगमंच कलाकार श्री राजेश तथा रंगमंच कलाकार श्री मुकेश्वर लाल शामिल थे।

स्लैम कविता प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में साहित्य क्षेत्र से श्रीमती हेमा पाइक, श्रीमती रेनू बाला तथा विदेश मामलों के कार्यालय की श्रीमती पूजा पासवान शामिल थीं।

लघु फिल्म एवं रील प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में वीडियोग्राफर एवं फोटोग्राफर श्री जनक, कट एंड क्रिएटर श्री सुरेश कुमार तथा फोटोग्राफर श्री एम. लक्ष्मण शामिल थे।

भाषण प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में विदेश मामलों के कार्यालय की श्रीमती शबनम सिंह, अंग्रेजी साहित्य की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. मंजू नायर तथा सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती शशमिता नाइक शामिल थीं।

नारा लेखन प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में इतिहासकार एवं कला संग्रहकर्ता श्री मुकेश्वर लाल, सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती विमला देवी तथा कलाकार श्री जे. एन. राजा शामिल थे।

लोक संगीत प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में कलाकार एवं मीडिया कर्मी श्री राकेश चन्द्र लाल, संगीतकार श्री गौतम धाली तथा संगीत में वरिष्ठ डिप्लोमा प्राप्त श्रीमती स्वप्ना रॉय शामिल थीं।

निर्णायक मंडल के सदस्यों ने प्रतिभागियों द्वारा प्रदर्शित रचनात्मकता, प्रतिभा एवं उत्साह की सराहना की तथा नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के विरुद्ध जागरूकता फैलाने के प्रभावी माध्यम के रूप में रचनात्मक अभिव्यक्ति के उपयोग के महत्व पर अपने विचार साझा किए। एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. मंजू नायर ने अपने विचार साझा करते हुए युवा प्रतिभागियों के प्रयासों की सराहना की तथा सकारात्मक सामाजिक संदेशों को बढ़ावा देने में साहित्य, कला एवं रचनात्मक अभिव्यक्ति के महत्व पर ज़ोर दिया।

इससे पूर्व, माई भारत, श्री विजय पुरम के ज़िला युवा अधिकारी श्री दीपक कुमार ने स्वागत भाषण दिया और मुख्य अतिथि, सम्मानित अतिथि, विशिष्ट अतिथियों, निर्णायक मंडल के सदस्यों, प्रतिभागियों एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। अपने संक्षिप्त संबोधन में उन्होंने युवाओं के बीच नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के विरुद्ध जागरूकता पैदा करने में सामूहिक प्रयासों के महत्व पर प्रकाश डाला तथा स्वस्थ, ज़िम्मेदार एवं नशामुक्त भारत के निर्माण के लिए युवाओं से ऐसी पहलों में सक्रिय रूप से भाग लेने का आह्वान किया।

श्री गोपाल चन्द्र बिस्वास, एपीएस (ओएसडी) ने परिचयात्मक संबोधन दिया और उपस्थित लोगों को "नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत" कार्यक्रम के उद्देश्यों एवं महत्व के बारे में जानकारी दी। उन्होंने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला तथा कहा कि विकसित भारत के विजन को प्राप्त करने के लिए स्वस्थ, ज़िम्मेदार एवं नशामुक्त युवा आबादी मूलभूत आवश्यकता है। उन्होंने पूरे कार्यक्रम का समन्वय भी किया।

कार्यक्रम को टीजीसीई के सहायक प्रोफेसर डॉ. सुनील सैनी तथा टीजीसीई की अतिथि व्याख्याता डॉ. सुनीता पाटिल का सहयोग प्राप्त हुआ। कार्यक्रम का कुशल संचालन टीजीसीई की सुश्री मेहक एवं सुश्री स्नेहा ने उत्साह एवं आत्मविश्वास के साथ किया। धन्यवाद ज्ञापन डॉ. सुनीता पाटिल ने प्रस्तुत किया।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार विभिन्न ज़िला स्तरीय प्रतियोगिताओं के सभी विजेताओं को मुख्य अतिथि एवं कार्यक्रम में उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा ट्रॉफी एवं प्रमाण–पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का समापन इस सामूहिक संकल्प "नशीली दवाओं को कहें ना, जीवन को कहें हां–नशा मुक्त युवा, विकसित भारत" के साथ हुआ।

सेनाओं की ताकत बढ़ेगी, 1.10 लाख करोड़ रुपये के हथियारों की खरीद को सैद्धांतिक मंजूरी

नई दिल्ली, 07 सितम्बर। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सोमवार की रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी डीएसी की बैठक हुई। इस बैठक में सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए करीब 1. 10 लाख करोड़ रुपए की रक्षा खरीद को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई। थलसेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन की मंजूरी दी गई है। नौसेना के लिए आधुनिक निगरानी 'अरुध्रा रडार' खरीदने को स्वीकृति दी गई है। वहीं वायुसेना के लड़ाकू विमानों की युद्धक क्षमता बढ़ाने से जुड़े प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं।

डीएसी ने कागज आधारित पहचान पत्र की जगह तकनीक आधारित स्मार्ट कार्ड को भी मंजूरी दी है। इस मंजूरी के बाद सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए कई अहम हथियारों, वाहनों, रडार और सैन्य प्रणालियों की खरीद का रास्ता साफ हो गया है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, डीएसी ने अलग–अलग खरीद प्रस्तावों को जरूरत की स्वीकृति (एओएन) दी है। दरअसल यह किसी उपकरण की खरीद की अंतिम मंजूरी नहीं, बल्कि आगे की खरीद प्रक्रिया शुरू करने के लिए महत्वपूर्ण शुरुआती मंजूरी है।

रक्षा मंत्रालय के अनुसार, भारतीय थलसेना के लिए कई महत्वपूर्ण उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी गई है। इनमें रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, उच्च गतिशीलता वाले वाहन, स्वचालित बारूदी सुरंग बिछाने वाली मशीनें, उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत्र पुल प्रणाली शामिल हैं। सीबीआरएन टोही वाहन ऐसे इलाकों में बेहद उपयोगी होंगे, जहां रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल या परमाणु पदार्थों से खतरा हो। ये वाहन ऐसे इलाके का पता लगाने, वहां मौजूद खतरे की पहचान करने, उसकी निगरानी करने और उस इलाके को चिन्हित करने में सक्षम होंगे। उच्च गतिशीलता वाले वाहन कठिन और चुनौतीपूर्ण इलाकों में सेना की आवाजाही और रसद पहुंचाने की क्षमता बढ़ाएंगे।

वहीं, स्वचालित बारूदी सुरंग बिछाने वाली मशीनें मुश्किल इलाकों में तेजी से बारूदी सुरंगें बिछाने में मदद करेंगी। सेना के लिए उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर भी खरीदे जाएंगे। इनका इस्तेमाल अलग–अलग इलाकों और जटिल सैन्य मिशन में किया जा सकेगा। इसके अलावा ट्रॉल टैंक और सर्वत्र पुल प्रणाली लड़ाकू सैनिकों को नदियों, नालों और अन्य बाधाओं को पार कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इन प्रणालियों की मदद से युद्ध के दौरान सैनिक और सैन्य वाहन तेजी से आगे बढ़ सकेंगे।

भारतीय नौसेना के लिए 'अरुध्रा रडार' खरीदने को मंजूरी दी गई है। इन रडारों को विभिन्न नौसैनिक हवाई स्टेशनों पर मौजूद पुराने हवाई मार्ग निगरानी रडारों की जगह लगाया जा सकता है। दरअसल, अरुध्रा एक आधुनिक निगरानी रडार है, जिससे नौसेना के हवाई ठिकानों की निगरानी क्षमता मजबूत होगी। नौसेना के लिए मरीन गैस टर्बाइन के डिजाइन और विकास तथा इसके बाद खरीद को भी मंजूरी दी गई है। मरीन गैस टर्बाइन युद्धपोतों की प्रणोदन प्रणाली यानी उन्हें आगे बढ़ाने वाली मुख्य प्रणाली का हिस्सा होती है। इसे स्वदेश में डिजाइन व विकास किया गया है। इससे नौसेना की विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। (इनपुट–आईएएनएस)

नागपुर में होगा आयुर्वेद दिवस का मुख्य आयोजन; थीम होगी–'स्वस्थ कल के लिए आयुर्वेद'

नई दिल्ली, 07 सितंबर (हि.स.)। इस वर्ष 23 सितंबर को महाराष्ट्र के नागपुर में आयुर्वेद दिवस का मुख्य समारोह आयोजित किया जाएगा। इस बार की थीम 'स्वस्थ कल के लिए आयुर्वेद' रखी गई है, जिसका उद्देश्य आयुर्वेद की समृद्ध परंपरा को भविष्य की स्वास्थ्य आवश्यकताओं से जोड़ना है।

केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने सोमवार को राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में 11वें आयुर्वेद दिवस के लिए कर्टेन रेज़र प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस आयुर्वेद दिवस के लिए देशव्यापी जनजागरूकता अभियान की औपचारिक शुरुआत के करते हुए युवाओं में इसके प्रचार–प्रसार पर जोर दिया।

प्रतापराव जाधव ने कहा कि आज पूरी दुनिया रोगों की रोकथाम, स्वस्थ जीवनशैली, पोषण, वेलनेस और समग्र स्वास्थ्य की ओर बढ़ रही है और इन क्षेत्रों में भारत के पास आयुर्वेद के रूप में समृद्ध ज्ञान और अनुभव है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद दिवस केवल भारत की परंपरा का उत्सव नहीं, बल्कि भविष्य की स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करने का अवसर भी है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'विकसित भारत' के विजन के अनुरूप स्वास्थ्य व्यवस्था केवल बीमारी के इलाज तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि स्वस्थ दिनचर्या, संतुलित आहार, मानसिक संतुलन और प्रकृति के साथ सामंजस्य को भी बढ़ावा देना चाहिए। मंत्री ने बताया कि इस वर्ष का अभियान तीन प्रमुख विषयों पर केंद्रित रहेगा–1. बेहतर स्वास्थ्य परिणामों के लिए समेकित स्वास्थ्य

सेवा, 2. आयुर्वेद में शोध, साक्ष्य और नवाचार, सामुदायिक कल्याण, 3. सतत जीवनशैली के लिए आयुर्वेद।

उन्होंने मीडिया से अपील करते हुए कहा कि आयुर्वेद से जुड़ी सही, वैज्ञानिक और प्रमाण आधारित जानकारी आम लोगों तक पहुंचाना बेहद आवश्यक है। यह अभियान घर–घर, स्कूलों, कॉलेजों, युवाओं, विशेषकर जेनजी तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों तक पहुंचे। उनका लक्ष्य है कि 11वां आयुर्वेद दिवस केवल सरकारी कार्यक्रम न रहकर जन आंदोलन और राष्ट्रीय स्वास्थ्य संचार अभियान बने।

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के कुलपति प्रो. संजीव शर्मा ने बताया कि आयुर्वेद दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय धन्वंतरि आयुर्वेद पुरस्कार 2026, एनआईए जयपुर की नई पहल, औषधीय पौधों के सुरक्षा दस्तावेज, त्वचा रोगों के लिए मानक उपचार दिशा–निर्देश, आयुष सर्विसेज सेक्टर रिपोर्ट, आयुष विज़न 2030, विभिन्न एमओयू और अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

दिल्ली से बाहर गुजरात के केवडिया में आयोजित होगा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह

नई दिल्ली, 07 सितम्बर। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह अपने 72 साल के इतिहास में पहली बार दिल्ली से बाहर आयोजित होगा। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि इस बार समारोह गुजरात के केवडिया में होगा, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 सितंबर को पुरस्कार प्रदान करेंगी। केवड़िया का नाम बदलकर एकता नगर कर दिया गया है और यहां सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा स्थापित की गई है जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' के नाम से मशहूर यह प्रतिमा 597 फुट ऊंची है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2018 में किया था।

वर्ष 1954 में पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया था और तब से अधिकतर पुरस्कार समारोह इसी स्थल पर हुए हैं। जुलाई में घोषित 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इस परंपरा से अलग होंगे। 'आर्टिकल 370' को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है, जबकि इसकी मुख्य अभिनेत्री यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार के लिए चुना गया है। मलयालम सुपरस्टार ममूटी और बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन को क्रमशः 'ब्रह्मयुगम' और 'चंदू चैंपियन' में उनकी भूमिकाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया जाएगा।

अभिनेता एवं फिल्मकार रणदीप हुड्डा को विनायक दामोदर सावरकर पर बनी फिल्म 'स्वातंत्र्य वीर सावरकर' के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक के पुरस्कार के लिए चुना गया है। तेलुगु फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' को ''संपूर्ण मनोरंजन वाली'' सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। वहीं, अरुण माथेश्वरन द्वारा निर्देशित और धनुष अभिनीत तमिल फिल्म 'कैप्टन मिलर' को ''राष्ट्रीय, सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों'' को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है।

एलपीजी रिफिल बुकिंग नियम में बदलाव, ग्रामीण उपभोक्ताओं को अब 25 दिन में मिलेगा सिलेंडर

नई दिल्ली, 07 सितम्बर। केंद्र सरकार ने सोमवार को घोषणा की कि ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू एलपीजी उपभोक्ता अब हर 25 दिन में रिफिल सिलेंडर बुक कर सकेंगे। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रिफिल बुकिंग का अंतराल शहरी क्षेत्रों के बराबर हो गया है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और पर्यटन राज्य मंत्री श्री सुरेश गोपी ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति में सुधार और रिफिल के लंबित बैकलॉग में उल्लेखनीय कमी को देखते हुए सरकार ने एलपीजी रिफिल बुकिंग पर पहले लगाए गए प्रतिबंध में ढील दी है।

अमेरिका–ईरान संघर्ष और इसके परिणामस्वरूप होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकाबंदी के कारण आपूर्ति पर दबाव के दौरान सरकार ने शहरी क्षेत्रों में हर 25 दिन में एक बार एलपीजी रिफिल बुक करने की अनुमति दी थी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को 45 दिनों तक इंतजार करना पड़ता था। गोपी ने फेसबुक पोस्ट में कहा, "हालांकि, वर्तमान में एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में सुधार और रिफिल के लंबित बैकलॉग में उल्लेखनीय कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस प्रतिबंध में ढील दी है। अब सभी घरेलू एलपीजी उपभोक्ता, चाहे वे शहरी हों या ग्रामीण, 25 दिनों के अंतराल पर रिफिल बुक कर सकते हैं।"

मंत्री ने पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को जारी एक पत्र की प्रति भी साझा की, जिसमें उन्हें संशोधित रिफिल बुकिंग अंतराल को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश दिया गया है। यह निर्णय वैश्विक स्तर पर तेल और गैस की आपूर्ति में व्यवधान से पैदा हुए ऊर्जा संकट के दौरान आपूर्ति प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कई कदमों के बाद एलपीजी की उपलब्धता में सुधार के बीच आया है।

इससे पहले जून में सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी की आपूर्ति पर लगाए गए प्रतिबंधों को वापस ले लिया था। पेट्रोलियम मंत्रालय ने ओएमसी को गैर–घरेलू पैक्ड एलपीजी की आपूर्ति को सामान्य स्तर पर बहाल करने का निर्देश दिया था, जो संघर्ष से पहले की स्थिति के समान था। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति पर प्रतिबंधों में भी ढील दी थी और उद्योगों को आपूर्ति संबंधी व्यवधानों के बीच सुचारु संचालन बनाए रखने में मदद करने के लिए संकट से पहले की खपत के 50 प्रतिशत तक आपूर्ति की अनुमति दी थी। अमेरिका–इजराइल द्वारा फरवरी में ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू होने और इसके बाद होर्मुज जलडमरूमध्य के जरिए जहाजों की आवाजाही बाधित होने के बाद ये प्रतिबंध लगाए गए थे। सरकार ने घरेलू एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने और वैश्विक तेल एवं ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के कारण होने वाली कमी को रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रावधान लागू किए थे। (इनपुट–आईएएनएस)

इसरो ने मीडिया के दावों का किया खंडन, कहा– न निजीकरण होगा, न महत्व घटेगा

नई दिल्ली, 07 सितम्बर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन–इसरो ने मीडिया की उन अटकलों और गलत सूचनाओं पर स्पष्टीकरण जारी किया है जिनमें इसरो के निजीकरण या उसकी भूमिका कम करने के प्रयासों की बात कही गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने कहा कि न तो उसका निजीकरण और न ही उसका महत्व कम किया जाएगा। अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी का उद्देश्य अंतरिक्ष कार्यक्रम को सक्षम बनाना है। इसरो ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों का उद्देश्य एक व्यापक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। इसलिए, इन सुधारों को निजीकरण के बजाय पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार और क्षमता वृद्धि के रूप में देखा जाना चाहिए। इसरो ने कहा कि परिपक्व और विस्तार योग्य तकनीकी क्षमताओं को भारतीय उद्योग द्वारा तेजी से विकसित किया जा सकता है। इससे बड़े पैमाने पर उत्पादन, व्यावसायीकरण, नवाचार और वैश्विक बाजारों तक पहुंच संभव होगी, जबकि इसरो के वैज्ञानिक और तकनीकी मानव संसाधन को उन्नत अनुसंधान, अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों और जटिल राष्ट्रीय मिशनों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिलेगी।

भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलूरू के शोधकर्ताओं ने समुद्री जल से यूरेनियम को अलग करने की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की

नई दिल्ली, 07 सितम्बर। भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बंगलूरू के शोधकर्ताओं ने समुद्री जल से यूरेनियम को अधिक प्रभावी तरीके से अलग करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। वैज्ञानिकों ने ऐसी विशेष स्लिप्ड सहसंयोजक कार्बनिक ढांचा (COF) झिल्लियों का अध्ययन किया है, जो यूरेनियम के ऑक्साइड आयनों को रोक सकती हैं, जबकि समुद्री जल में मौजूद अन्य सामान्य आयनों को गुजरने देती हैं।

यह खोज इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि परमाणु ऊर्जा के लिए यूरेनियम प्रमुख ईंधन है। उपलब्ध अनुमानों के मुताबिक भूमि पर करीब 75 लाख टन यूरेनियम मौजूद है, जबकि समुद्री जल में इसकी अनुमानित मात्रा करीब 450 करोड़ टन है। ऐसे में समुद्र भविष्य में यूरेनियम का बड़ा वैकल्पिक स्रोत बन सकता है।

समुद्री जल से यूरेनियम निकालना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें अनेक प्रकार के आयन बहुत अधिक मात्रा में मौजूद होते हैं। अब तक विकसित कई तकनीकें यूरेनियम को मजबूत रासायनिक बंधनों के जरिए पकड़ने का प्रयास करती रही हैं, लेकिन IISc की नई तकनीक झिल्ली की नैनोस्तरीय संरचना और आयनों की आवाजाह को नियंत्रित करने पर आधारित है।

शोधकर्ताओं ने आणविक स्तर पर आयनों की जलयोजन

संरचना, मुक्त–ऊर्जा अवरोध और झिल्ली से उत्पन्न घर्षण का अध्ययन किया। पाया गया कि COF की परतों को विशेष तरीके से खिसकाने पर ऐसी सूक्ष्म संरचना बनती है, जो यूरेनियम आयनों को प्रभावी रूप से रोक सकती है।

इस तकनीक का उपयोग केवल परमाणु ईंधन के लिए ही नहीं, बल्कि भूजल से यूरेनियम प्रदूषण हटाने में भी किया जा सकता है। इससे पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों के समाधान की नई संभावनाएं खुल सकती हैं। यह शोध योगेंद्र कुमार और बीनू वर्गीज ने प्रोफेसर प्रबल के. मैती के मार्गदर्शन में किया है, जिसमें एक्सेंचर लैब्स, बंगलूरू ने भी सहयोग दिया।